गन्ने का बकाया चुकाने के लिए यूपी की मिलों पर प्रेशर

लोकसभा चुनाव से पहले 40 लाख किसानों को लुभाना अखिलेश सरकार का मकसद

मन मोहन राय *लखनऊ*

उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार गन्ना किसानों की 2,700 करोड़ रुपए की बकाया पेमेंट का भुगतान करने के लिए राज्य की प्राइवेट मिलों पर दबाव बढ़ा रही है। राज्य सरकार घाटे में चल रही शुगर इंडस्ट्री की अपील नहीं सुन रही है। दरअसल, वह लोकसभा चुनाव से पहले 40 लाख किसानों को लुभाना चाहती है। उत्तर प्रदेश देश में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यह इंडस्ट्री राज्य की इकनॉमी में बड़ी भूमिका निभाती है। एनालिस्ट्स का कहना है कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले किसानों के साथ खुद को दिखाना चाहती है। मिल मालिकों का कहना है कि बढ़ते घाटे और क्रेडिट न मिलने की वजह से वे बकाया पैसा चुकाने की हालत में नहीं हैं। राज्य की 35,000 करोड़ रुपए की शुगर इंडस्ट्री को सरकारी बैंकों ने नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है।

यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सी पी पटोदिया ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में सभी कंपनियों की शुगर यूनिट्स को पिछले कुछ क्वार्टर्स में नुकसान हुआ है। इस वजह से हम किसानों की बकाया रकम नहीं चुका पाए हैं। सरकारी बैंकों ने राज्य की शुगर इंडस्ट्री को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है और हमें लोन देना बंद कर दिया है।'

> चीनी की हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 35 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि इसका सेल प्राइस 30-31 रुपए प्रति किलोग्राम का है
>
> **अबिनाश वर्मा,** डायरेक्टर जनरल, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन

पटोदिया ने बताया कि एसोसिएशन ने बकाया रकम चुकाने में मदद के लिए राज्य सरकार से इंडस्ट्री को 2,400 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट-फ्री लोन दिलाने की गुजारिश की है। हालांकि, यह डिमांड शायद ही पूरी हो। वहीं, सरकार मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर सकती है। 2012-13 सीजन में मिलों ने 22,463 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा था। इसमें से अभी इन्हें 2,700 करोड़ रुपए का भुगतान करना बाकी है।

एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने मिलों को 16 अगस्त तक पेमेंट करने का निर्देश दिया था। इस पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी है। जानकारों का कहना है कि राज्य सरकारों ने राजनीतिक हितों की वजह से स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस (एसएपी) में बढ़ोतरी की थी। इस प्राइस पर मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा ने बताया कि पिछले 3 साल में एसएपी 70 फीसदी बढ़ाया गया है, जबकि चीनी का रीटेल प्राइस केवल 17 फीसदी बढ़ा है। उन्होंने कहा, 'चीनी की हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 35 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि इसका सेल प्राइस 30-31 रुपए प्रति किलोग्राम का है।' पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 2012 में गन्ने का एसएपी बढ़ाकर 240 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था, जो 2007 में 125 रुपए पर था। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पिछले साल नवंबर में इसमें 40 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी।

Economic Times (Hindi)

22/8/13